Himachal Dastak 08-02-2026

अब नहीं भटकेंगे पेंशनर, समस्याओं का होगा समाधान

दफ्तरों के चक्कर काटने वाले कर्मचारियों को राहत देने के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने शुरू की विशेष मुहिम

हिमाचल दस्तक ▮ धर्मशाला

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अब अपने सेवानिवृत्त अधिकारियों और पेंशनर्स के मामले में एक्शन मोड में आ गया है। सालों की सेवा के बाद पेंशन और अपने हक के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने वाले कर्मचारियों को राहत देने के लिए बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने एक विशेष मुहिम शुरू की है।

▮ पेंशन और एरियर की बाधाएं होंगी दूर

इसी कड़ी में शनिवार को धर्मशाला में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर 18 फरवरी को होने वाले मंथन-मंथन की रूपरेखा तैयार की गई। बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने स्पष्ट किया कि 18 फरवरी को होने वाली बैठक महज एक औपचारिक चर्चा नहीं, बल्कि परिणाम देने वाला मंच होगी। इसमें पेंशनर्स से जुड़े संवेदनशील मुद्दों जैसे पारिवारिक पेंशन, लंबित एरियर, चिकित्सा बिलों का भुगतान और तकनीकी बाधाओं को मौके पर ही सुलझाने की कोशिश की जाएगी। डॉ. शर्मा ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि हर मामले को संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ देखा जाए ताकि बुजुर्ग पेंशनर्स को सम्मानजनक समाधान मिले। बैठक के दौरान रणनीति बनाई गई कि जो मामले बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में हैं, उनका निपटारा तुरंत प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। वहीं, जिन फाइलों पर प्रदेश सरकार या अन्य विभागों की मंजूरी अनिवार्य है, उन्हें बोर्ड खुद आगे बढ़कर संबंधित अथॉरिटी के पास पैरवी के लिए भेजेगा। डॉ. शर्मा के अनुसार, इस पूरी कवायद का उद्देश्य पेंशनर्स की समस्याओं को व्यावहारिक और विधिसम्मत तरीके से हल करना है।

पेंशनर के सम्मान में बोर्ड का सार्थक कदम

बोर्ड के इस कदम से हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों में उम्मीद की नई किरण जगी है। जानकारी के अनुसार बोर्ड अपने पूर्व कर्मचारियों के अनुभवों का सम्मान करता है और उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। शनिवार को हुई इस तैयारी बैठक में सचिव सचिव सहित बोर्ड के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने आगामी 18 फरवरी की बैठक को सुव्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण बनाने का रोडमैप साझा किया।

एलडीआर टेस्ट को लेकर पांगी के एसएमसी शिक्षकों ने की मांग, किलाड़ में विशेष परीक्षा केंद्र स्थापित किया जाए

पांगी। प्रदेश में सेवारत एसएमसी शिक्षकों के लिए प्रस्तावित लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट को लेकर पांगी ट्राइबल उपमंडल से एक महत्वपूर्ण मांग सामने आई है। पंगवाल एकता मंच पांगी ने प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग से आग्रह किया है कि पांगी के कठिन भौगोलिक और मौसम संबंधी हालात को देखते हुए आईटीडीपी पांगी के मुख्यालय किलाड़ में एक विशेष परीक्षा केंद्र स्थापित किया जाए। पंगवाल एकता मंच के अध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर ने इस संबंध में हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव और सचिव (शिक्षा) को ईमेल के माध्यम से पत्र भेजकर स्थिति से अवगत कराया है। पत्र में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की 20 दिसंबर, 2025 की अधिसूचना का हवाला देते हुए बताया गया कि स्कूल शिक्षा निदेशालय द्वारा सेवारत एस एमसी शिक्षकों के 1472 पदों के लिए एलडीआर टेस्ट आयोजित किया जा रहा है, जिसकी परीक्षा तिथि 22 फरवरी निर्धारित है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि अभी तक केवल दो परीक्षा केंद्र शिमला और धर्मशाला अधिसूचित किए गए हैं, जबकि पांगी ट्राइबल उपमंडल से लगभग 105 सेवारत एसएमसी शिक्षक इस परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक हैं। इन शिक्षकों को शिमला या धर्मशाला तक पहुंचने और वापस लौटने में परीक्षा दिवस सहित कम से कम 5 दिन लगेंगे। त्रिलोक ठाकुर ने पत्र में स्पष्ट किया है कि वर्तमान समय में पांगी घाटी में मौसम की स्थिति अत्यंत खराब बनी हुई है। हाल ही में हुई भारी बर्फबारी के बाद भी क्षेत्र की अधिकांश संपर्क सड़कें अभी तक वाहनों के लिए पूरी तरह बहाल नहीं हो पाई हैं, जिससे शिक्षकों की यात्रा जोखिमपूर्ण हो सकती है। इसके साथ ही एक और गंभीर पहलू यह भी सामने रखा गया है कि यदि शिक्षक एक सप्ताह तक स्कूलों से अनुपस्थित रहते हैं, तो इससे पांगी जैसे दुर्गम क्षेत्र के स्कूलों में पठन-पाठन व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होगी, जिसका सीधा नुकसान छात्रों को उठाना पड़ेगा। इन सभी विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पंगवाल एकता मंच ने सरकार से मांग की है कि शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को निर्देश देकर किलाड़ में एक अस्थाई/विशेष परीक्षा केंद्र स्थापित किया जाए ताकि पांगी क्षेत्र के शिक्षकों को राहत मिल सके।

पंजाब केसरी
SUN,08 FEBRUARY 2026
EDITION: KANGRA KESARI, PAGE NO. 3

18 को होने वाली बैठक की तैयार की रूपरेखा : राजेश

धर्मशाला, 7 फरवरी (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अब अपने सेवानिवृत्त अधिकारियों और पैंशनर्ज की सुध लेने के लिए पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। साल की सेवा के बाद पैंशन और अपने हक के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने वाले कर्मचारियों को राहत देने के लिए बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने एक विशेष मुहिम शुरू की है।

इसी कड़ी में शनिवार को धर्मशाला में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर 18 फरवरी को होने वाले महा-मंथन की रूपरेखा तैयार की गई। बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने स्पष्ट किया कि 18 फरवरी को होने वाली बैठक महज एक औपचारिक चर्चा नहीं, बल्कि परिणाम देने वाला मंच होगी। इसमें पैंशनर्ज से जुड़े संवेदनशील मुद्दों जैसे पारिवारिक पैंशन, लंबित एरियर, चिकित्सा बिलों का भुगतान और तकनीकी बाधाओं को मौके पर ही सुलझाने की कोशिश की जाएगी।

धर्मशाला : बोर्ड अधिकारियों से बैठक करते अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा। (ब्यूरो)

बेर्ड के अधिकार क्षेत्र वाले मामलों का प्राथमिकता पर होगा निपटारा

***बैठक** के दौरान रणनीति बनाई गई कि जो मामले बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में हैं, उनका निपटारा तुरंत प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। बैठक में सहायक सचिव सहित बोर्ड के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।*

Divya Himachal 08-02-2026

अब नहीं भटकेंगे पेंशनर्ज, दहलीज पर होगा समस्याओं का समाधान

दिव्य हिमाचल ब्यूरो-धर्मशाला

राजेश शर्मा

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अब अपने सेवानिवृत्त अधिकारियों और पेंशनर्ज की सुध लेने के लिए पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। सालों की सेवा के बाद पेंशन और अपने हक के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने वाले कर्मचारियों को राहत देने के लिए बोर्ड अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने एक विशेष मुहिम शुरू की है। इसी कड़ी में शनिवार को धर्मशाला में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर 18 फरवरी को होने वाले महा-मंथन की रूपरेखा तैयार की गई। डा. राजेश शर्मा ने स्पष्ट किया कि 18 फरवरी को होने वाली बैठक महज एक औपचारिक चर्चा नहीं, बल्कि परिणाम देने वाली बैठक होगी। इसमें पेंशनर्स से जुड़े संवेदनशील मुद्दों जैसे पारिवारिक पेंशन, लंबित एरियर और तकनीकी बाधाओं को मौके पर ही सुलझाने की कोशिश की जाएगी।

बोर्ड खुद करेगा पैरवी

बैठक के दौरान रणनीति बनाई गई कि जो मामले बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में हैं, उनका निपटारा तुरंत प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। वहीं, जिन फाइलों पर प्रदेश सरकार या अन्य विभागों की मंजूरी अनिवार्य है, उन्हें बोर्ड खुद आगे बढ़कर संबंधित अथॉरिटी के पास पैरवी के लिए भेजेगा।

Dainik Jagran 08-02-2026

18 को सुलझेंगी पेंशनरों की समस्याएं

पारिवारिक पेंशन, लंबित एरियर, चिकित्सा बिलों के मामले निपटाएंगे : डा. राजेश

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला में पेंशनरों की समस्याओं के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा। साथ हैं अन्य अधिकारी • जागरण

जागरण संवाददाता, धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए एक विशेष मुहिम शुरू की है।

शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने बताया कि यह पहल उन कर्मचारियों को राहत देने के लिए है, जो वर्षों की सेवा के बाद पेंशन और हक के लिए कार्यालयों के चक्कर काटते रहे हैं। इसी संदर्भ में, शनिवार को धर्मशाला में अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें 18 फरवरी को होने वाले महामंथन की रूपरेखा तैयार की गई।

डा. राजेश शर्मा ने स्पष्ट किया कि 18 फरवरी को होने वाली बैठक केवल औपचारिक चर्चा नहीं होगी, बल्कि यह एक परिणाम देने वाला मंच होगा। इस बैठक में पेंशनर्स से जुड़े संवेदनशील मुद्दों जैसे पारिवारिक पेंशन, लंबित एरियर, चिकित्सा बिलों का भुगतान और तकनीकी बाधाओं को मौके पर ही सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर मामले को संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ देखा जाए, ताकि बुजुर्ग पेंशनर्स को सम्मानजनक समाधान मिल सके।

बैठक के दौरान यह रणनीति बनाई गई कि जो मामले बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में हैं, उनका निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। वहीं, जिन फाइलों पर प्रदेश सरकार या अन्य विभागों की मंजूरी आवश्यक है, उन्हें बोर्ड खुद संबंधित अथारिटी के पास पैरवी के लिए भेजेगा। बोर्ड अध्यक्ष के अनुसार, इस पूरी कवायद का उद्देश्य पेंशनर्स की समस्याओं को व्यावहारिक और विधिसम्मत तरीके से हल करना है।

बोर्ड के इस कदम से हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों में उम्मीद की नई किरण जगी है। डा. राजेश शर्मा ने कहा कि बोर्ड पूर्व कर्मचारियों के अनुभवों का सम्मान करता है और उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है।

शनिवार को हुई इस तैयारी बैठक में बोर्ड सचिव डा. मेजर विशाल शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे, जिन्होंने आगामी 18 फरवरी की बैठक को सुव्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण बनाने का रोडमैप साझा किया।

लिपिक वर्ग में की जाए नई भर्ती

- देहरा में एनजेडआईईए प्रदेशस्तरीय विस्तारित सचिवालय बैठक में उठाई मांग
- बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआइ का किया विरोध ओपीएस भी हो बहाल

संवाद सहयोगी, जागरण • देहरा: नार्दर्न जोन इंश्योरेंस एंप्लाइज एसोसिएशन (एनजेडआईईए) शिमला ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी) में लिपिक वर्ग में नई भर्ती की मांग की है। संगठन का कहना है कि दफ्तरों में कार्य का बोझ बढ़ता जा रहा है, जबकि स्टाफ की संख्या लगातार घट रही है। यदि शीघ्र भर्ती नहीं की गई, तो ग्राहकों को उचित सेवा प्रदान करना कठिन हो जाएगा। कर्मचारी नेताओं ने स्पष्ट किया कि नए संशोधित श्रम कानून मजदूरों के अधिकारों को सीमित करने और कंपनियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं, जिन्हें किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

इसके साथ ही, बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) का विरोध करते हुए यूनियन ने कहा कि एलआइसी देशवासियों के विश्वास और उनकी बचत से बनी है, इसे विदेशी हाथों में सौंपना देशहित में नहीं है। ये मांगें शनिवार को देहरा में आयोजित एसोसिएशन की प्रदेशस्तरीय विस्तारित सचिवालय बैठक में उठाई गईं। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष नरेंद्र धीमान ने की। उन्होंने कहा कि 1995 की पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को भी शीघ्र बहाल किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, सरकार को एलआइसी में लाए जा रहे एफपीओ के निर्णय को भी वापस लेना चाहिए।

मंडल सचिव प्रदीप मिन्हास ने कहा कि आज एलआइसी जिस स्थिति में है, वह कर्मचारियों की मेहनत और जनता के विश्वास का परिणाम है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इन मांगों को अनसुना किया, तो शिमला मंडल का हर कर्मचारी सड़क पर उतरकर आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगा। बैठक में शिमला मंडल की सभी शाखाओं से कर्मचारी नेता उपस्थित रहे।